

दिखेगी विरासत व विकास की झलक

गीडा के **स्थापना दिवस पर** कंपनियों के उत्पादों के साथ गीता प्रेस का भी लगेगा स्टाल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के स्थापना दिवस के मौके पर 30 नवंबर और एक दिसंबर को लगने वाले दो दिवसीय ट्रेड शो में गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश की विरासत के साथ ही देश की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की भी झलक दिखेगी। कई नामी कंपनियों व विभिन्न जिलों के ओडीओपी और स्थानीय उत्पाद तो प्रदर्शनी में दिखेंगे ही गीता प्रेस भी अपना स्टाल लगाएगा। गीता प्रेस की तरफ से

स्टाल लगाने के लिए गीडा को सहमति पत्र भी भेजा जा चुका है। यह पहली बार होगा कि गीडा के कार्यक्रम में आध्यात्मिक पुस्तकों के स्टाल लगाए जाएंगे। स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दो दिन में इसके अंतिम रूप ले लेने की उम्मीद है। खुद मंडलायुक्त अनिल ढोंगरा और गीडा की सीईओ अनुज मलिक तैयारियों की निगरानी कर रही हैं।

मुख्यमंत्री की पहल पर मंडलायुक्त अनिल ढोंगरा ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गीडा दिवस के तैयारियों के संबंध में बैठक करते हुए निर्देशित किया कि ट्रेड शो में गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ मंडल के एक जिला एक उत्पाद के अतिरिक्त अन्य स्थानीय उत्पादों को स्थान दिया जाए। उन्होंने उपायुक्त उद्योग से स्थानीय उत्पाद के उद्यमियों की जानकारी प्राप्त की। बैठक में बताया गया कि गोरखपुर

बोतलें रिसाइकिल कर बनाई जाएंगी नई

सहजनवां : गीडा के सेक्टर 27 में एस्पलएमजी ग्रुप की तरफ से पुरानी बोतलों को रिसाइकिल करके नई बोतलें बनाई जाएंगी। फैक्ट्री के संचालन से तीन सौ से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गीडा के स्थापना दिवस में मुख्यमंत्री इस कंपनी को भी भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र सौंपेंगे। एस्पलएमजी ग्रुप की ओर से फैक्ट्री लगाने के लिए करीब 70 हजार वर्ग मीटर भूमि की मांग



की गई है, जिसे उपलब्ध कराने की सभी तैयारियां गीडा ने पूरी कर ली हैं। इस फैक्ट्री में पुरानी और खराब प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल कर फिर से नई बोतल बनाई जाएगी। फैक्ट्री लगाने के लिए करीब 200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और फैक्ट्री के संचालन से तीन सौ से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। संस्था की तरफ से गीडा के स्थापना दिवस पर स्टाल भी लगाया जाएगा। गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक का कहना है कि एस्पलएमजी ग्रुप की तरफ से बोतलों को रिसाइकिल करके नई बोतलें बनाई के लिए भूमि मांगी गई है। सेक्टर 27 में उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इसकी स्थापना से करीब तीन सौ लोगों को रोजगार मिलेगा।

मंडल से 25 और आजमगढ़ व बस्ती मंडल से दस-दस स्थानीय उद्यमी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी आदि अधिकारी मौजूद रहे।

उधर, मंगलवार को गीडा के एसीओ आरडी पांडेय ने चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों और उद्यमियों के साथ बैठक कर उन्हें ट्रेड शो में प्रतिभाग करने की अपील की। एसीओ ने बताया कि दो दिवसीय ट्रेड शो में 10 गुणे 10 वर्ग फीट के स्टाल के लिए 50 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि गीडा में स्थापित सभी प्रमुख यूनिटों के उत्पादों के साथ पूर्वांचल के सभी जिलों के ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी में प्रतिभागिता सुनिश्चित हो। चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के महासचिव आकाश ने अधिक से अधिक इकाइयों की प्रतिभागिता का

आश्वासन देने के साथ ही सूक्ष्म और लघु श्रेणी की यूनिटों को फ्री में स्टाल देने की बात रखी। चैंबर के अध्यक्ष आरएन सिंह का कहना है कि ट्रेड शो में सूक्ष्म और लघु उद्योगों से 50 हजार रुपये का शुल्क लेना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसे लेकर मंडलायुक्त के साथ हुई बैठक में भी वार्ता हो चुकी है। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष दीपक कारीवाल का कहना है कि शुल्क को लेकर गीडा सीईओ से उद्यमी अपनी बात रखेंगे। ट्रेड शो में स्टाल से उत्पादों की ब्रांडिंग होनी चाहिए।

मुख्य सचिव से मिलेंगे उद्यमी, बताएंगे समस्याएं : ट्रेड शो के दौरान उद्यमी मुख्य सचिव एवं आयुक्त अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास मनोज कुमार सिंह से मिलकर संवाद करेंगे और अपनी समस्याओं को साझा करते हुए उनके निस्तारण की मांग करेंगे। इसे लेकर लघु उद्योग

भारती के मंडल अध्यक्ष दीपक कारीवाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 30 नवंबर को बैठक के लिए समय मांगा है। मंडल अध्यक्ष ने वार्ता के बिंदु की जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर, 2022 के बाद लगे उद्योगों को इलेक्ट्रिक ड्यूटी में छूट नहीं मिल रही है। वहीं प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक का पद खाली है, जिससे उद्यमियों के कार्य बाधित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश एमएसएमई नीति 2022 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उद्यमियों की रकम फंसी हुई है। ऐसे में इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण जरूरी है। उन्होंने बताया कि लघु उद्योग भारती की ओर से यह भी मांग की जाएगी कि गोरखपुर में भी एमएसएमई विभाग के एक कार्यालय की स्थापना की जाए।